

प्रेषक

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-24 अक्टूबर, 2007

विषय : नगर पंचायत, बदीनाथ के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2005-06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 691/V-श0वि0-06-31(सा0)/06, दिनांक 25-3-06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, बदीनाथ जनपद चमोली के अन्तर्गत दो कार्यों हेतु रु०-48.97 लाख की लागत के आगमन के विपरीत रु०-42.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 21.35 लाख की धनराशि अयमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं० 1932/श.वि.नि-485-2005/लेखा /07-08 दिनांक 07 अगस्त 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अयमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरांत, शासनादेश दिनांक 25-3-06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों हेतु रु. 21.35 लाख (रुपये इक्कीस लाख पैंतिस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्त पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अयमुक्त करेगी।
2. शासनादेश सं० 691/V-श0वि0-06-31(सा0)/06, दिनांक 25-3-06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगमनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अदेतलर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-03-08 तक उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपखर्चिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. कार्यों की शनयवृद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/निर्माण एजेंसी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगमन गणित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाधीनक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समकित विकास-आयोजनागत-191-स्वतन्त्र निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार नीति को सहायता-03-नगरों का समकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद "20 सहायक अनुदान/अनुदान/ राज सहायता" के नाम डाला जायेगा।

कमश:

3- यह आदेश वित्त विभाग के असा0सा0-544/XXVII(2)/2006, दिनांक-20 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

सं0-392(1)/IV-सा0वि0-07, तददिनांक। 24/10/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकॉस्ट, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रभारी अधिकारी अधिकारी, नगर पंचायत, बदीनाथ।
10. बजट राजपौषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मायावती डकरियाल)
अनु सचिव।